

अजीमुनिस्सा और अन्य

बनाम

उप संरक्षक, निष्क्रान्त सम्पतियाँ, जिला देवरिया और अन्य

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., जे. एल. कपूर, पी. बी. गर्जेन्द्रगडकर, के.

सुब्बा राव और के.एन. वांचू, जे.जे.)

निष्क्रान्त संपत्ति-अमान्य अध्यादेश के तहत स्वतः निहित होना, बाद के अधिनियमों के तहत निहित होना जारी रखना -वैध होना निर्वासित ब्याज का पृथक्करण समग्र संपत्ति गैर-उन्मूलन हित की संपत्ति की बिक्री-चाहे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो-यू पी. निष्क्रमण संपत्ति प्रशासन अध्यादेश, 1949 (1949 का यू.पी. ग्रेडी नैन्स I), धारा. धारा. 2(सी) और 5-इवेक्यू प्रो-पार्टी का प्रशासन (मुख्य आयुक्त के प्रांत) अध्यादेश 1949 (1949 का अध्यादेश XI)। 5-निष्पादन संपत्ति का प्रशासन (ची कमिश्नर के प्रांत) संशोधन अध्यादेश 1989 (1949 का अध्यादेश XX), धारा. 8-निष्क्रिय संपत्ति का प्रशासन अध्यादेश 1949 (अध्यादेश XXVII, 1949), 7 और 8-सटीक संपत्ति का प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश 2950 (अध्यादेश IV, 1950), धारा. 4-निष्क्रिय संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (XXXI 1950), 1.7 और 8-निष्क्रिय संपत्ति का प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1960 का 2), 1.2-निष्क्रिय हित (पृथक्करण)

अधिनियम, 1951 (1951 का LXIV)), धाराआरओ-भारत का संविधान, कला। 19 और 31.

एक K जिसके पास उत्तर प्रदेश में कुछ संपत्तियों में 0-2-3 की हिस्सेदारी थी, 1947 में पाकिस्तान चला गया। सक्षम अधिकारी ने संपत्ति में K की हिस्सेदारी को अलग करने के लिए इवैक्यूई इंटेरेस्ट (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 के तहत कार्यवाही की। दावेदार के का हिस्सा खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरी संपत्ति को धारा के तहत नीलाम कर दिया। अधिनियम के धारा 10 के तहत याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि के एक निष्क्रमणकर्ता नहीं था, कि संपत्ति समग्र संपत्ति नहीं थी, कि अधिनियम के तहत कार्यवाही शून्य थी और अधिनियम की धारा 10 शून्य थी क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 31 व 19^{1/4}1^{1/2}1^{1/4}f^{1/2} का उल्लंघन करती थी। संविधान के 31 और 19(1). उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि संपत्ति में K का हित 1949 के यू.पी. अध्यादेश 1 के तहत स्वचालित रूप से अभिरक्षण में निहित हो गया था और यह निहितार्थ 1949 के केंद्रीय अध्यादेश XII द्वारा जारी रखा गया था। 1949 के केंद्रीय अध्यादेश XXVII और 1950 के केंद्रीय अधिनियम XXXI और किसी भी कानूनी द्वारा निहितीकरण में दोष को 1960 के केंद्रीय अधिनियम । द्वारा ठीक किया गया था, कि संपत्ति तदनुसार समग्र संपत्ति थी और पृथक्करण अधिनियम के तहत उचित रूप से नीलाम की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर दिया

कि 5.प्र. 1949 का अध्यादेश और केन्द्रीय. 1940 का अध्यादेश XII, विधायी सक्षमता के अभाव में अमान्य था और उनके प्रावधानों के तहत कानून में कोई निहितार्थ नहीं हो सकता था जिसे बाद के अध्यादेशों और अधिनियमों द्वारा जारी रखा जा सकता था।

अभिनिधारित किया गया कि संपत्ति समग्र संपत्ति थी और पृथक्करण अधिनियम के तहत उचित रूप से नीलाम की गई थी। चूंकि के यू.पी. अध्यादेश के एक (सी) के तहत निष्क्रांत थी, उसकी संपत्ति स्वचालित रूप से 5 के तहत अभिरक्षण में निहित हो गई थी और इसे 1949 के केंद्रीय अध्यादेश XII के तहत जारी किया गया था। भले ही ये दोनों अध्यादेश विधायी अक्षमता के लिए खराब थे। इसके तहत पॉट पोर्टेड निहितीकरण को 1940 के केंद्रीय अध्यादेश XXVII के तहत और उसके बाद 1950 के केंद्रीय अधिनियम XXXI के तहत जारी रखा गया था और इस तरह के निहितार्थ में किसी भी कानूनी दोष को 1960 के केंद्रीय अधिनियम । द्वारा ठीक किया गया था।

अभिनिधारित हुआ आगे वह धारा. पृथक्करण अधिनियम के 10(ए) में संविधान की धारा 31 और 19(1)(एफ) का उल्लंघन में शून्य नहीं था चूंकि याचिकाकर्ता खरीदने के लिए तैयार नहीं थे के हिस्से को सक्षम

अधिकारी ने संपत्ति सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने में उचित कार्य किया।

मूल क्षेत्राधिकार: 1958 की याचिका संख्या 56 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका।

ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री और जी. सी. माथुर, याचिकाकर्ता की तरफ से
सी.के. डैफटोरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, आर.बी. उत्तरदाताओं
की तरफ से नानक चंद और आर. एच. डेबर संख्या 1 से 3 की आेर से

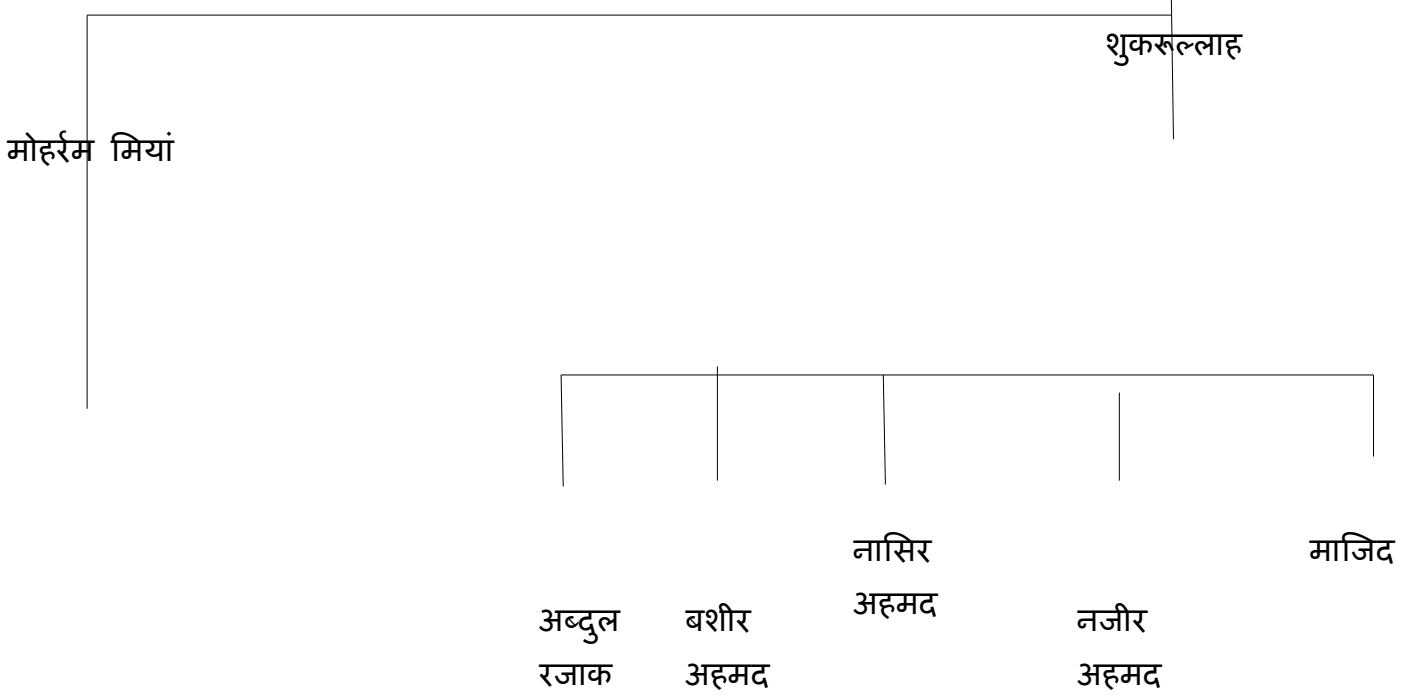
सी.के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, हरनाम सिंह और 1.
एन. श्रॉफ प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से।

जे. पी. गोयल, उत्तरदाताओं संख्या 5 से 10 के लिए।

1960. 26 अक्टूबर. कोर्ट का फैसला सुनाया गया।

कपूर जे.-यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत छह व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका है जिसमें उन रिकॉर्डों को मंगाने के लिए उत्प्रेषण याचिका की मांग की गई है जिसमें कुछ आदेश पारित किए गए थे और विवाद में संपत्ति को बहाल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए एक परमादेश जारी किया गया था। निम्नलिखित वंशावली तालिका मामले को समझने में सहायता करेगी

हिन्गन मियां



खुदा बख्श

नूरी मिया..रहमत बीबी

अजीमुन्निसा..मकबूल
अहमद

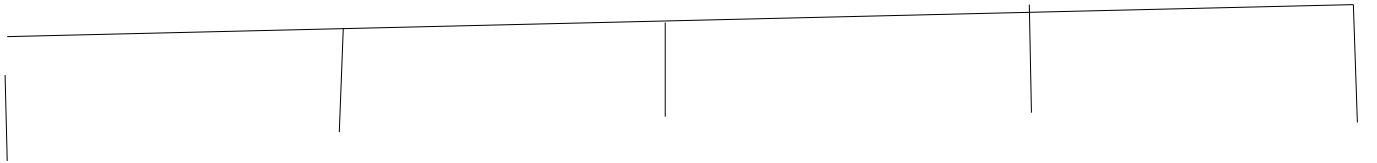
खातून बीबी..अब्दुल
बरकत

तघमा बीबी



खदीजा बीबी

शमसुन्निसा



लुत्फ अहमद

मोहम्मद अहमद

आयशा खातून

कमरुन्निसा

तहजीबुन्निसा

अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विवादित संपत्तियों को नूरी मियां ने हासिल किया था और उनकी मृत्यु के बाद कुछ मुकदमेबाजी हुई थी, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप डिप्टी क्यू-प्रतियोगियों के शेयर निम्नानुसार तय किए गए थे: - एन। निष्क्रांत 0.1.9

(ए) रहमत बीबी, विधवा 0-1.6

(बी) तगमा बीबी 0-1.5

(सी) खातून बीबी 0-1-9

(डी) अजीमुन्निसा 0-1.9

(ई) शुक्रुल्लाह 0-5.4

(च) खुदा बक्श 0.4.3

28 अगस्त, 1942 को, शकरू-उल्लाह ने अपने बेटों के पक्ष में एक वक्फ-अलाल-औलाद बनाया और अब्दुल रज्जाक को मुतवाली (ट्रस्टी) के रूप में नामित किया। 1945 में शकर-उल्लाह की मृत्यु हो गई। वर्ष 1947 में, याचिकाकर्ताओं में से एक खातून बीबी कराची चली गई और उनके द्वारा बताया गया प्रत्यक्ष कारण यह था कि वह अपने पति की बीमार बहन की देखभाल करने के लिए गई थीं जो कराची में थीं।

22 नवम्बर 1949 को एक नोटिस जारी किया गया खातून बीबी, उनके मैनेजर और नौकरों ने उन्हें विस्थापित घोषित कर दिया और उनसे अपनी संपत्ति पर कब्जा छोड़ने का आह्वान किया। "भटनी नूरी चीनी मिल्स, जमींदारी और काश्तकारी भूमि" के रूप में वर्णित। उनके पति अब्दुल बरकत ने आपत्तियां दाखिल कीं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन आपत्तियों पर कोई आदेश पारित किया गया हो. 17 अप्रैल, 1950 को, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का XXXI), जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाता है, लागू हुआ। खातून बीबी को 5 जुलाई, 1950 को निष्क्रांत संपत्ति के उप संरक्षक, दूरिया द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि क्यों उन्हें निष्क्रांत घोषित नहीं किया जाना चाहिए और क्यों उनकी सभी संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए। आरोप है कि नोटिस में संपत्ति का कोई विवरण नहीं था और इसलिए यह अप्रभावी था। उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्य का खंडन किया गया है। उनके हलफनामे में यह कहा गया था कि संपत्ति पूरी तरह से निर्दिष्ट और पहचानी गई थी और 5 जुलाई 1950 का नोटिस अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए था; खातून बीबी की संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति बन गई थी और वर्ष 1949 में स्वचालित रूप से निहित हो गई थी। इस नोटिस के खिलाफ अब्दुल बरकत ने भी आपत्तियां दाखिल कीं लेकिन 7 मार्च के एक आदेश द्वारा, आदेश था 1951, इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। आदेश निम्नानुसार था:-

"आपति खारिज। स्वीकार्य रूप से बीबी खातून निष्क्रांत है। नोटिस की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है और नोटिस में वर्णित संपत्ति (पर्याप्त रूप से हालांकि पूरी तरह से नहीं) को एतद्द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया जाता है।

इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं लिया गया। 8 जनवरी, 1953 को अधिनियम की धारा 7 के तहत एक नोटिस बशीर अहमद और नासिर अहमद के खिलाफ जारी की गई थी और 14 दिसंबर, 1955 के एक आदेश द्वारा, उन दोनों को निष्क्रांत घोषित कर दिया गया था और संपत्तियों में उनके हितों को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया गया था। सहायक अभिरक्षक (न्यायिक) के इस आदेश से पता चलता है कि नोटिस में संपत्तियों का वर्णन किया गया था और यह कहा गया था कि बशीर अहमद और नासिर अहमद दोनों निष्क्रांत थे और संपत्ति में उनकी हित निष्क्रांत संपत्ति थी, लेकिन चूंकि यह समग्र संपत्ति थी, इसलिए निश्चित हिस्सा थे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। इन दोनों विस्थापितों द्वारा यूपी के इवैक्यू प्रॉपर्टी के अभिरक्षण के पास अपील की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है।

इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा निकासी हित (पृथक्करण) अधिनियम (1951 का 64) के तहत कार्यवाही की गई, जिसे इसके बाद पृथक्करण अधिनियम कहा जाएगा। के तहत नोटिस जारी किये गये। 15

फरवरी 1954 को पृथक्करण अधिनियम के धारा 6, और जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, उन्होंने संपत्ति में विभिन्न शेयरों का दावा करते हुए अलग-अलग दावे दायर किए। सक्षम अधिकारी ने 20 मार्च, 1956 के अपने आदेश द्वारा, विभिन्न विस्थापितों और गैर-निष्क्रमितों के हिस्सों की घोषणा की और यह भी माना कि चूंकि दावेदार विवादग्रस्त संपत्ति में निष्क्रमित लोगों के हिस्सा खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इसके लिए एकमात्र तरीका उपलब्ध था। विभाजन सार्वजनिक नीलामी द्वारा हुआ था। उन्होंने निर्देश दिया कि वक्फ अल-औलाद की विषय वस्तु को किस प्रकार अलग किया जाए। संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में उन्होंने सहायक मूल्यांकन अधिकारी और अधीक्षक, मूल्यांकन कार्यालय, खान मार्केट, नई दिल्ली द्वारा किए गए मूल्यांकन का उल्लेख किया, जो कि पूर्व में रु. निर्माण और भूमि के लिए 7,41,300 और बाद में रु. मशीनरी, भूमि सहित 14,15,000 और इमारतों और फिर अस्थायी रूप से मूल्यांकन रुपये पर तय किया गया। 14,15,000 और अंतिम मूल्यांकन के लिए मामले को फिर से अधीक्षक, मूल्यांकन कार्यालय को भेज दिया। उन्होंने खातून बीबी का हिस्सा 0-2-3 और नीलामी द्वारा भी तय किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के पास अपील की गई। 13 अगस्त, 1956 को, विवादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 को रुपये में बेच दी गई थी। 16,05,000. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता अजीमुन्निसा और अब्दुल वाहिद ने आपत्तियां दाखिल कीं लेकिन उन्हें 1 अक्टूबर 1956 को सक्षम अधिकारी

ने खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के पास पुनरीक्षण लिया गया लेकिन 24 अक्टूबर को दोनों आपतियां खारिज हो गईं। 1957 इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने 27 सितंबर, 1956 को अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की वैधता और बिक्री का आदेश देने वाले सक्षम अधिकारी के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर उनके पक्ष में निर्णय लिया गया लेकिन याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता लापरवाही के दोषी थे क्योंकि वे पांच साल तक अपने अधिकारों को लेकर सोते रहे थे और जब कोई और नोटिस जारी नहीं किया जा सका तो उन्होंने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। अधिनियम के तहत और पारित विभिन्न आदेशों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आजी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, मुन्निसा और अन्य। सहायक संरक्षक (') और अपीलीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत में विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया लेकिन ये दोनों याचिकाएं 10 फरवरी, 1958 को खारिज कर दी गईं।

याचिकाकर्ता अब अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में आए हैं। 7 मार्च, 1951 को याचिकाकर्ता खातून बीबी की आपतियों को खारिज करने वाले सहायक संरक्षक, देवरिया के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण

(1) की रिट के लिए 32; (2) सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 20 मार्च 1956 और अपीलीय अधिकारी के दिनांक 24 अक्टूबर 1957 के आदेश को रद्द करने के लिए और (3) बिक्री कार्यवाही को रद्द करने के लिए। 13 मार्च, 1956 को संपत्ति की बिक्री समाप्त हो रही थी और (4) उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को संपत्ति बहाल करने का निर्देश देने वाला एक परमादेश दिया गया था। (1) ए.आई.आर. 1957 सभी 561.

याचिकाकर्ताओं की ओर से तीन प्रश्न उठाए गए: (1) कि संपत्ति पृथक्करण अधिनियम के तहत समग्र संपत्ति नहीं थी; (2) खातून बीबी और बशीर अहमद और नासिर अहमद के शेयरों को कानून के विभिन्न

प्रावधानों और इसलिए प्रावधान के तहत वैध रूप से निष्क्रांत ब्याज घोषित नहीं किया गया था। पृथक्करण अधिनियम के नियम लागू नहीं हुए; (3) पृथक्करण अधिनियम की धारा 10(a¹/₂¹/₄iii) जहां तक यह गैर-निकासी संपत्ति की बिक्री का निर्देश देती है, अनुच्छेद 19¹/₄1¹/₂¹/₄f¹/₂ का उल्लंघन करती है इसलिए असंवैधानिक था। मामले का निर्णय मुख्य रूप से इस निर्णय पर निर्भर करता है कि विवादित संपत्ति समग्र संपत्ति थी या नहीं। पृथक्करण अधिनियम के 2(डी) समग्र संपत्ति को परिभाषित किया गया है: धारा 2(डी) "" समग्र संपत्ति का अर्थ है कोई भी संपत्ति जो या कोई भी संपत्ति जिसमें हित को निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया है या निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का XXXI) के तहत

अभिरक्षण में निहित किया गया है और -

(i) जिसमें निष्क्रमित व्यक्ति के हित में उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सह-हिस्सेदार या भागीदार के रूप में रखी गई संपत्ति में अविभाजित हिस्सेदारी शामिल है, जो निष्क्रांत व्यक्ति नहीं है।"

और "निकासी हित" को धारा 2^{1/4}e^{1/2} में परिभाषित किया गया है।

धारा 2^{1/4}e^{1/2} एक समग्र संपत्ति के संबंध में ""निष्कासी हित" का अर्थ है अधिकार, शीर्षक और हित एयू उस संपत्ति में निष्क्रांत है। विवादित संपत्ति का हिस्सा निष्क्रांत संपत्ति थी, इसलिए निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में पारित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। विवादित संपत्ति संयुक्त प्रांत में स्थित है और उस प्रांत में पहला कानून बनाया गया था। जैसा कि तब था, संयुक्त प्रांत निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अध्यादेश, 1949 (यू.पी. अध्यादेश संख्या 1 1949) था, जो गोबो अलिशिंगुज 24 जून, 1949 को प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश में निष्क्रांत और निष्क्रमित संपत्ति की परिभाषा थी जिसे बाद के अध्यादेशों और अधिनियमों में जारी रखा गया है। उस अध्यादेश के धारा 5 में संयुक्त प्रांत में स्थित सभी निष्क्रांत संपत्ति स्वचालित रूप से अभिरक्षण में निहित हो जाती है और ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को अभिरक्षण की ओर से धारण करने वाला माना जाता है (ई. 6(2))। चूँकि खातून बीबी यू.पी. अध्यादेश की धारा 5 2(e) के तहत एक निष्कासन थी, उसकी

संपत्ति स्वचालित रूप से धारा के तहत अभिरक्षण में निहित हो गई। लेकिन इस अध्यादेश की वैधता को याचिकाकर्ताओं द्वारा अजीमुनिसा बनाम असिस्टेंट अभिरक्षण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। चुनौती का आधार यह था कि संविधान अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची में निष्क्रांत संपत्ति से संबंधित सूचियों में कोई प्रविष्टि नहीं थी और संविधान अधिनियम के धारा 104 के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा कोई सार्वजनिक अधिसूचना नहीं थी। 1935. यह अध्यादेश, यानी 1949 का यू.पी. अध्यादेश 1, 23 अगस्त 1949 को समाप्त हो गया।

13 जून, 1949 को, गवर्नर जनरल ने निकासी संपत्ति प्रशासन (मुख्य आयुक्तों के प्रांत) अध्यादेश XII, 1949 को प्रख्यापित किया और एक प्रस्ताव पारित होने के बाद यू.पी. विधानमंडल के अंतर्गत इसे 23 अगस्त, 1949 को अध्यादेश XX, 1949 द्वारा उत्तर प्रदेश तक बढ़ा दिया गया। संविधान अधिनियम की धारा 103. पूर्व की धारा 5 में संपत्ति को अभिरक्षण में निहित करने का प्रावधान इस प्रकार है:-

धारा 5(1) इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, एक प्रांत में स्थित सभी निष्क्रांत संपत्ति उस प्रांत के संरक्षक में निहित होगी।

(2) जहां, इस अध्यादेश के शुरू होने से ठीक पहले, किसी प्रांत में कोई भी निष्क्रांत संपत्ति ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उस प्रांत में लागू किसी भी संबंधित कानून के तहत संरक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले

किसी भी व्यक्ति में निहित हो गई थी, वहां निष्क्रांत संपत्ति, इस अध्यादेश के प्रारंभ पर, इस अध्यादेश के तहत प्रांत के लिए नियुक्त संरक्षक में निहित माना जाएगा"। अध्यादेश XX की धारा 8 में धाराएं जोड़ी गईं। 1949 के अध्यादेश XII के धारा 41 जो कि व्यावृत्ति प्रावधान था। (1) ए.आइ.आर. 1957 इलाबाद 561.

इस प्रकार धारा 5 के तहत यू.पी अध्यादेश की समाप्ति के बावजूद खातून बीबी की संपत्ति को 1949 के अध्यादेश XII के प्रावधानों के तहत अभिरक्षण में निहित माना गया था। लेकिन इस अध्यादेश 1949 के यू.पी.

अध्यादेश 1 के समान संवैधानिक दोष से (1949 के XII को 1949 के अध्यादेश XX द्वारा संशोधित) का सामना करना पड़ा। 25 अगस्त, 1949 को, "निष्कासन" से संबंधित आइटम 31-बी को भारत सरकार अधिनियम (तीसरा संशोधन) अधिनियम 1949 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था और इस प्रकार यह संवैधानिक शून्य भर गया। 18 अक्टूबर, 1949 को गवर्नर जनरल ने निकासी संपत्ति प्रशासन अध्यादेश (1949 का XXVII) प्रख्यापित किया। इसने 1949 के अध्यादेश XII को निरस्त कर दिया। इस अध्यादेश की धारा 7 में निष्क्रांत संपत्ति और धारा की घोषणा का प्रावधान है। निष्क्रांत संपत्ति को अभिरक्षण में निहित करने के लिए। धारा 7 का सुसंगत भाग हैं-

धारा. 7(1) जहां अभिरक्षण की राय है कि कोई भी संपत्ति इस

अध्यादेश के अर्थ के तहत निष्क्रांत संपत्ति है, तो वह उसके बारे में नोटिस देने के बाद, ऐसे तरीके से दे सकता है जो इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित किया जा सकता है। , और मामले की ऐसी जांच करने के बाद जैसी मामले की परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं, ऐसी किसी भी संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने का आदेश पारित करें" धारा 8 के तहत निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई कोई भी संपत्ति संरक्षक में निहित होगी।"

(2) जहां अध्यादेश के प्रारंभ से ठीक पहले इस अनुसार, प्रांत में कोई भी निष्क्रांत संपत्ति, इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी भी कानून के तहत अभिरक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति में निहित थी, अध्यादेश के प्रारंभ पर, निष्क्रांत संपत्ति को नियुक्त अभिरक्षण में निहित माना जाएगा या इस अध्यादेश के तहत प्रांत के लिए नियुक्त माना जाएगा और आगे भी नियुक्त किया जाएगा 80 निहित "ये प्रावधान पिछले अध्यादेशों से भौतिक रूप से भिन्न थे क्योंकि अभिरक्षण में कोई स्वचालित निहितार्थ नहीं था। इस प्रकार 1949 के अध्यादेश XII के तहत किसी भी निहितीकरण को 1949 के अध्यादेश XXVII के तहत माना जाएगा जैसे कि अध्यादेश निहित होने की तारीख पर लागू हुआ हो।

निकासी प्रशासन के 1950 का संपत्ति (संशोधन) अध्यादेश IV, धारा 8 का 1949 के अध्यादेश XXVII को एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था इस अनुभाग का प्रासंगिक भाग 100 8050 वह उनका और

OIME का स्वागत करते हैं

धारा 8(2) जहां इस अध्यादेश के शुरू होने से ठीक पहले, प्रांत में किसी भी संपत्ति को इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी भी कानून के तहत अभिरक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित किया गया था, संपत्ति, इस अध्यादेश के प्रारंभ होने पर इस अध्यादेश के अर्थ के अंतर्गत घोषित निष्क्रांत संपत्ति मानी जाएगी और नियुक्त संरक्षक में निहित मानी जाएगी या नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इस अध्यादेश के तहत प्रांत के लिए एड, और ऐसा ही निहित रहेगा। बशर्ते कि, इस अध्यादेश के प्रारंभ में, किसी भी प्रांत के संरक्षक के समक्ष निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अध्यादेश, 1949 (1949 का XII) की धारा 8 के तहत या उसके तहत किसी संपत्ति के संबंध में कोई दावा लंबित हो। इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी भी अन्य संबंधित कानून के बावजूद, इस अध्यादेश या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, ऐसे दावे का निपटारा इस तरह किया जाएगा जैसे कि इस अध्यादेश की धारा 2 में निहित निष्क्रांत संपत्ति और निष्कासन की परिभाषाएँ दी गई हों। उस पर लागू हो जाओ।"

अध्यादेश के इस प्रावधान के तहत प्रभाव निहित करने का तात्पर्य यह था कि इसे इस अध्यादेश के अंतर्गत माना जाता था।

18 अप्रैल, 1950 को निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950

(1950 का XXXI), जिसे अधिनियम कहा जाता है, संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने 1949 के अध्यादेश XXVII को निरस्त कर दिया। निष्क्रांत और निष्क्रांत संपत्ति की परिभाषाएँ अध्यादेश XXVII के समान हैं। अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 भी समान पदों पर हैं। निष्क्रांत संपत्ति को अभिरक्षण में निहित करने के प्रावधान भी संशोधित धारा के समान ही थे। अध्यादेश XXVII के 8. धारा 58 निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है। इसलिए धारा 8(2)का परिणाम यह था कि अध्यादेश XXVII

के तहत निहित संपत्ति को माना गया था अधिनियम के संगत प्रावधान के तहत निहित किया जाएगा।

27 फरवरी, 1960 को इस अधिनियम में संशोधन किया गया निष्क्रांत संपत्ति का प्रशासन (संशोधन) & अन्य 1960 का अधिनियम 1. धारा में उपधारा (2-ए) जोड़ी गई जो निम्नलिखित शर्तों में था:

(2-ए) उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संपत्ति जो किसी भी कानून के तहत निरस्त की गई है, जो किसी भी व्यक्ति में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित होने का तात्पर्य है। कपूर जे किसी भी राज्य में अभिरक्षण की शक्तियों का उपयोग करते हुए, ऐसे कानून या किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश में किसी भी दोष या अमान्यता के बावजूद, सभी उद्देश्यों के लिए वैध रूप से उस व्यक्ति में निहित माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के कानून के

प्रावधान संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे और ऐसी संपत्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इस अधिनियम के अर्थ के तहत घोषित निष्क्रांत संपत्ति मानी जाएगी और तदनुसार, कोई भी आदेश या अन्य कार्रवाई की जाएगी। ऐसी संपत्ति के संबंध में अभिरक्षण या किसी अन्य प्राधिकारी को वैध और कानूनी रूप से बनाई या ली गई मानी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि 1949 का यूपी अध्यादेश 1, 1949 का केंद्रीय अध्यादेश XII और 1949 का केंद्रीय अध्यादेश XX निकासी और निकासी

के संबंध में गवर्नर और गवर्नर-जनरल की विधायी क्षमता के रूप में अमान्य थे। संपत्ति के मामले वांछित थे; और वह सब उप-धारा 8 में से (2-ए) 1960 के अधिनियम 1 द्वारा जोड़ा गया 8 किसी भी निहितार्थ को बचाने के लिए था जो कि अध्यादेश XXVII के तहत हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य संवैधानिक अक्षमता के कारण किसी भी अमान्यता को ठीक करना नहीं था और यह कानून संविधान के बिना बनाया गया था - राष्ट्रीय प्राधिकार मान्य नहीं किया जा सका. सगीर अहमद बनाम द स्टेट ऑफ यूपी. (') का संदर्भ दिया गया था, जहां पृष्ठ 728 पर कूलीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेडशन्स, वॉल्यूम से निम्नलिखित कथन दिया गया था। 1, पृष्ठ 384 (नोट):-

"असंवैधानिकता के लिए शून्य कानून मृत है और बाद के संशोधन द्वारा इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता है (1) [1955] 1 धारा.सी.आर.

707. 728. संवैधानिक उद्देश्य को हटाते हुए संविधान की 102 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टें को फिर से लागू किया जाना चाहिए, इसे एक ठोस कानून माना गया।

म.प्र.वि. सुंदररामियर कार्ड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का भी हवाला दिया गया। जहां विधायिका की अक्षमता के कारण असंवैधानिकता और संवैधानिक निषेधों की अवहेलना के बीच अंतर किया गया था।

जवाब में उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि खातून बीबी को जारी किए गए नोटिस में कोई खामी थी और उनकी संपत्ति का उचित और पर्याप्त रूप से वर्णन किया गया था और 1960 के अधिनियम 1 ने निहितार्थ को मान्य किया और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दोष और अमान्यता, यदि कोई हो, उसके मामले पर लागू विभिन्न कानूनों में कमियाँ को हटा दिया। खातून बीबी को पहला नोटिस 22 नवंबर, 1949 के अध्यादेश XXVII के तहत था, जिसके खिलाफ उनके पति अब्दुल बरकत ने आपत्तियां दायर कीं, लेकिन जाहिर तौर पर इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। दूसरा नोटिस जो 5 जुलाई 1950 को दिया गया था, उसमें संपत्ति को पर्याप्त रूप से निर्दिष्ट किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ अब्दुल बरकत द्वारा फिर से आपत्तियां उठाई गईं, लेकिन 7 मार्च, 1951 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गईं, और उस आदेश के खिलाफ कोई आगे अपील या संशोधन या कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई और

कोई भी दोष और कमियां, चाहे वह कानून की हो या अन्यथा, अब नहीं की जा सकेंगी। उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संपत्ति का पर्याप्त रूप से वर्णन किया गया था, हालांकि पूरी तरह से नहीं, और उस संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य की सत्यता का विरोध किया कि संपत्ति का उचित वर्णन किया गया था और अजीमु निनिसा बनाम सहायक संरक्षक (पृ. 568, पैरा 10) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जो इंगित करता है कि संपत्ति का कोई विवरण नहीं था। जिस दृष्टि से हम इस विवाद को ले रहे हैं, वह अपनी जीवंतता खो देता है।

उत्तरदाताओं द्वारा ली गई दूसरी दलील यह थी कि धारा 8^{1/4}2^{1/2}1^{1/4}a^{1/2} की प्रविष्टि द्वारा 1960 के अधिनियम 1 प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था और किसी भी निष्क्रांत संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित किया वैध जाना गया था।

ऐसे कानून में किसी भी दोष या अमान्यता के बावजूद अभिरक्षण को मान्य किया गया था और उस अधिनियम (1960 का अधिनियम 1) के प्रारंभ पर, जिस संपत्ति को अभिरक्षण में निहित माना जाता था, उसे निष्क्रांत संपत्ति माना जाता था, जिसे इसके अर्थ के भीतर घोषित किया गया था। अधिनियम और अभिरक्षण द्वारा किया गया कोई भी आदेश या कार्रवाई वैध रूप से की गई या की गई मानी जानी चाहिए।

"अभिप्राय" शब्द के कई अर्थ हैं इसका मतलब काल्पनिक है, जो कपूर जे उपकरण के चेहरे पर दिखाई देता है; स्पष्ट और कानूनी आयात नहीं और इसलिए कोई भी कार्य जो किसी शक्ति के प्रयोग में किया जाना चाहिए, उस शक्ति के भीतर किया गया माना जाएगा, भले ही वह शक्ति प्रयोग करने योग्य न हो; डिकर बनाम एंगरस्टीन। अतः अभिप्राय उस बात का सूचक है जो ऊपर से दिखाई देता है या स्पष्ट है, भले ही कानून के अनुसार ऐसा न हो। इसका मतलब यह है कि उस समय जब अधिनियम में विवादित संपत्ति को अभिरक्षण में निहित करने का इरादा था, भले ही शक्ति प्रयोग करने योग्य नहीं थी, अधिनियम का धारा 8(2) निहितीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर ऐसे बनाता है मानो वह धारा के तहत निहित हो रहा हो। अधिनियम की धारा 8(2) और इसलिए अमान्यता के आधार पर हमले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यू.पी. अध्यादेश 1949 की धारा 5 के तहत खातून बीबी की संपत्ति जो निष्क्रांत हो गई थी। यूपी प्रांत के निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक में निहित किया गया था। उस अध्यादेश को समाप्त होने की अनुमति दी गई थी। 1949 के केंद्रीय अध्यादेश XII द्वारा, जिसे बाद में संशोधित किया गया, निष्क्रांत संपत्ति के निहितार्थ को उस अध्यादेश के तहत माना गया, जिसे बदले में धारा के तहत निरस्त कर दिया गया। 1949 के अध्यादेश XXVII का 55 जो एक वैध कानून था। धारा द्वारा. उस अध्यादेश के 8(2) में पिछले अध्यादेश के तहत निहित होने को उस अध्यादेश के तहत माना गया था जैसे कि वह निहित होने

की तारीख पर लागू था। 1949 के अध्यादेश XXVII को अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसमें 8(2) में निहित करने के प्रावधान शामिल थे, जिसे अध्यादेश के संबंधित प्रावधान के समान कहा गया था और इसलिए कानून के एक समूह द्वारा मूल निहित माना जाना था जैसा कि (1) (1876) 3 अध्याय। डी. 600, 603.

यदि पहली बार निहित होने पर अधिनियम लागू था। अज़ीमुन्निसा के मामले में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने निहितार्थ को अमान्य माना क्योंकि 1949 के अध्यादेश XII और यहां तक कि अध्यादेश 1949 के डिप्टी सीयू-XX के समय तक विधायी क्षमता की कमी थी, और यहां तक कि धारा 8¹/₄2¹/₂ में माने गये प्रावधानों द्वारा भी 1949 के अध्यादेश XXVII या 1950 के अधिनियम XXXI के 8(2) में कोई वैध निहितार्थ नहीं था, क्योंकि मूल निहितीकरण खराब था। हम यह तय करना अनावश्यक समझते हैं कि क्या धारा के प्रावधान को उचित माना जाएगा। अधिनियम का 8(2) या 1949 का अध्यादेश XXVII निहितीकरण को वैधता देने के लिए पर्याप्त था। हमारी राय में, अधिनियम में पेश की गई धारा 8(2-ए) निहितीकरण को वैध बनाती है, क्योंकि यह उस निहितीकरण को वैधता प्रदान करती है जो कि 1949 के अध्यादेश XXVII के परिणामस्वरूप हुआ था, भले ही यह केवल स्पष्ट रूप से ऐसा था और कानून में ऐसा नहीं था, क्योंकि 'अभिप्राय' का तात्पर्य यही है।

धारा 8¹/₄2¹/₂ का प्रभाव वह है जिसे धारा के तहत निहित माना जाता है। 1949 के अध्यादेश XXVII के 8(2) और जिसे धारा के तहत निहित माना जाएगा। अधिनियम के 8 जिसने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, मूल निहित या न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश में किसी भी अमान्यता के बावजूद, अभिरक्षक में वैध रूप से निहित निष्क्रांत संपत्ति मानी जाएगी और संपत्ति के संबंध में अभिरक्षक द्वारा किया गया

कोई भी आदेश वैध माना जाएगा. इस प्रकार (1) जो निहित होना चाहिए उसे मान्य करने के लिए अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है; (2) 1949 के अध्यादेश XXVII के 8.8(2) के तहत निहित या काल्पनिक निहितार्थ में सभी दोष या अमान्यता को हटा देता है। अधिनियम की धारा 8(2) जिसने अध्यादेश को निरस्त कर दिया; (3) निहितार्थ के संबंध में किसी भी न्यायालय के विपरीत डिक्री और निर्णयों को अप्रभावी बना देता है; (4) संपत्ति को अपने माने गये प्रभाव से निष्क्रांत संपत्ति बना देता है; और (5) संपत्ति के संबंध में अभिरक्षण द्वारा पारित सभी आदेशों को मान्य करता है। अधिनियम को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव और 1960 के अधिनियम 1 के वैध प्रभाव के कारण सगीर अहमद के मामले ("") का कोई उपयोग नहीं होगा। हमने जो विचार किया है उसमें अन्य प्रश्न जीवित नहीं हैं और खातून बीबी का हिस्सा वैध रूप से निष्क्रांत संपत्ति होना बरकरार रखा जाना चाहिए।

संरक्षक में निहित. इसलिए विवादित संपत्ति धारा में दी गई समग्र संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है। 2(डी) और इसे अमान्य नहीं माना जा सकता।

तब यह तर्क दिया गया कि संपत्ति की बिक्री से गैर-निष्क्रमित लोगों को अवैध रूप से उनके समर्थक से वंचित कर दिया गया था। इसलिए धारा 10, सीएल. (ए) प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31 और

19(1)(एफ) का उल्लंघन करता है। ये विवाद भी उतना ही है जिसमें कुछ तत्व न हो। धारा 10 का प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:-

"किसी भी कानून या अनुबंध या किसी सिविल कोर्ट या अन्य प्राधिकारी के किसी डिक्री या आदेश में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, सक्षम अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, ऐसे सभी उपाय कर सकता है जैसे वह किसी समग्र संपत्ति में दावेदारों के हितों से इवैक्यू के हितों को अलग करने के उद्देश्य से आवश्यक समझ सकता है, और विशेष रूप से, -

(ए) सह-हिस्सेदार या भागीदार के किसी भी दावे के मामले में, -

(i) अभिरक्षण को निर्देश दें कि वह दावेदार को समग्र संपत्ति में उसके हिस्से के संबंध में निर्धारित धनराशि का भुगतान करे या ऐसी संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र वाले सिविल कोर्ट में जमा करे और संपत्ति का

कब्जा अभिरक्षण को दे। दावेदार सिविल न्यायालय में जमा राशि वापस ले सकता है; या

(ii) संपत्ति में निष्क्रांत व्यक्ति के हिस्से के संबंध में मूल्यांकन की गई धनराशि का भुगतान करने पर दावेदार को संपत्ति हस्तांतरित करना; या

(iii) संपत्ति बेचें और बिक्री आय को अभिरक्षण और दावेदार के बीच वितरित करें। संपत्ति में विस्थापित और दावेदार के हिस्से के अनुपात में; या

(iv) निष्क्रांत व्यक्ति और दावेदार के शेयरों के अनुसार संपत्ति का विभाजन करें और निष्क्रमित व्यक्ति और दावेदार को आवंटित शेयरों का कब्जा प्रदान करें क्रमशः अभिरक्षण और दावेदार को।" इस प्रकार सक्षम अधिकारी के लिए चार विकल्प खुले थे: इनमें से (1) गैर-निष्कासित लोगों के हिस्से के मौद्रिक मूल्य का अभिरक्षण द्वारा भुगतान। परिणामस्वरूप यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है गैर निष्क्रमणकर्ताओं को, और (2) निष्क्रमणकर्ताओं द्वारा कोडियन को निष्क्रमितों के हिस्से के धन मूल्य का भुगतान उसके लिए उपलब्ध नहीं था। इस मामले में पूर्व में न तो दावा किया गया था और न ही टेपेट सेने कोस्टोडियन से गैर-इवैकोर्स को इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने की उम्मीद की जा सकती थी। 20 मार्च, 1956 के कॉम्पेटेंट अधिकारी के आदेश से पता चलता है कि

गैर। ईवा के सह-हिस्सेदार सेस्टोडियन को ईवा के शेयरों के मौद्रिक मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे, शेष विकल्पों में से तीसरा विकल्प संपत्ति का विभाजन था, लेकिन प्रकृति के कारण वर्तमान मामले में यह भी संभव नहीं था। समग्र संपत्ति जिसमें चीनी मिल शामिल थी जिसे चीजों की प्रकृति के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता था। नतीजतन, पृथक्करण का एकमात्र उपलब्ध तरीका अभिरक्षण, ले. द्वारा संपत्ति की बिक्री और बिक्री आय के विभाजन द्वारा अपनाया गया था। इन परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की कार्रवाई को अनुचित या अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे कानून के अधिकार के बिना गैर-निकाले गए लोगों को उनकी संपत्ति से वंचित करना नहीं कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप उक्त याचिका असफल हुई खर्चे सहित खारिज की जाती है।

याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **घनश्याम शर्मा, न्यायिक अधिकारी** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।